केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क- bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
# भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463
भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :49 अंक 124 गुरूवार 26 नवम्बर 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

## एक नजर

### साइबर सेल ने वापस कराये ठगी के 50 हजार रूपये



–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । लालगंज थाना क्षेत्र में साइबर ठगी के शिकार एक व्यक्ति को 50 हजार रुपये वापस मिल गए। कोर्ट के आदेश पर रकम उनके बैंक खाते में लौटाई गई। लालगंज थाना क्षेत्र के सजनाखोर निवासी सीताराम पुत्र रामवेलास के साथ साइबर ठगों ने 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी। शिकायत मिलने पर लालगंज पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और संबंधित बैंक से संपर्क किया।

प्रभारी निरीक्षक दिनेश चंद्र चौधरी के नेतृत्व में साइबर सेल की टीम ने तकनीकी और कानूनी कार्रवाई की। टीम ने बैंक के साथ मिलकर ठगी की रकम संबंधित खाते में होल्ड कराई। बुधवार दोपहर 2 बजे जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट के आदेश से पूरी रकम सीताराम के बैंक खाते में वापस कराई गई।

रकम मिलने पर सीताराम ने लालगंज पुलिस और साइबर सेल की टीम को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक की साइबर अपराधों के प्रति विशेष रुचि और साइबर सेल की त्वरित कार्रवाई से उन्हें रकम वापस मिल सकी।

### पत्रकार को पितृ शोक



–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश कुमार पाण्डेय के पिता शत्रुघ्न पाण्डेय (83 वर्ष) का लंबी बीमारी के बाद सोमवार की रात्रि लगभग 10.30 बजे निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पत्रकार जगत, सामाजिक क्षेत्र और शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई। निधन की सूचना मिलते ही पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और परिचितों ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

बस्ती प्रेस क्लब के अध्यक्ष विनोद उपाध्याय, जयंत मिश्रा, महामंत्री महेंद्र तिवारी तथा राघवेंद्र मिश्रा 'पप्पू' ने शत्रुघ्न पाण्डेय के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न पाण्डेय एक सच्चे समाजसेवी, सरल स्वभाव और नेक विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जीवनभर अपने सिद्धांतों और आदर्शों को महत्व दिया तथा कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका सामाजिक जीवन लोगों के प्रति समर्पण और सेवा भावना से प्रेरित रहा।

शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में वशिष्ठ पाण्डेय, जीशान हैदर रिजवी, विपिन मिश्रा, अनिल कुमार पाण्डेय, विवेक श्रीवास्तव, राजेश कुमार पाण्डेय, अभिनव कुमार दूबे, प्रवीण पाण्डेय, अनिल श्रीवास्तव, अरुणेश श्रीवास्तव, बसंत लाल, बबुंदर यादव सहित अनेक पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं शुभचिंतक शामिल रहे। सभी ने दिवंगत शत्रुघ्न पाण्डेय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

# राधे–राधे तो शुरुआत है, सपा के लिए अब राम नाम सत्य का समय– योगी



लखनऊ (आभा)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि दो नावों की सवारी करने वाले डूबते हैं। अखिलेश को अयोध्या जाने से पहले रामभक्तों और हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि राधे–राधे तो शुरुआत है, सपा के लिए अब राम नाम सत्य का समय आ रहा है। मथुरा में राधे–राधे, अयोध्या में जय श्रीराम और काशी में हर–हर महादेव कहना आस्था के अनुरूप है, जबकि राम नाम सत्य विदाई के समय कहा जाता है। मुख्यमंत्री बुधवार को एक टीवी मीडिया समूह को दिए साक्षात्कार में सियासी माहौल गरमा दिया है। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि दो नावों की सवारी करने वाले डूबते हैं। अखिलेश को अयोध्या जाने से पहले रामभक्तों और हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि राधे–राधे तो शुरुआत है, सपा के लिए अब राम नाम सत्य का समय आ रहा है। मथुरा में राधे–राधे, अयोध्या में जय श्रीराम और काशी में हर–हर महादेव कहना आस्था के अनुरूप है, जबकि राम नाम सत्य विदाई के समय कहा जाता है। मुख्यमंत्री बुधवार को एक टीवी मीडिया समूह को दिए साक्षात्कार में बोल रहे थे।

योगी ने सपा की राजनीति को परिवार तक सीमित बताते हुए उसके पीडीए की नई व्याख्या की। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सपा की राजनीति परिवार के इर्द–गिर्द घूमती है, जबकि भाजपा का मतदाता हर वह राष्ट्रवादी नागरिक है, जो संविधान और देश की विरासत का सम्मान करता है। उनकी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन देश और समाज के सामने चुनौती आने पर उसका सामना करना संन्यासी का दायित्व है।

मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने इसे चुनाव से पहले ही विफल करार देते हुए कहा कि एक तरफ दोनों दलों की बैठकें चल रही हैं और दूसरी तरफ प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। दोनों दलों पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने प्याज भी खाया और जूता भी। योगी ने स्पष्ट किया कि भाजपा और एनडीए के सहयोगी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशियों का चयन पार्टी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा विदेशी घुसपैठियों को अपना मानती है, जबकि मतदाता सूची में केवल पात्र भारतीय नागरिकों के नाम होने चाहिए।

## रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र



–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । युवाओं को रोजगार के अवसरों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय बस्ती एवं सर्वोदय इंटर कॉलेज नेवादा के संयुक्त तत्वावधान में सर्वोदय इंटर कॉलेज नेवादा रुधौली बस्ती के विद्यालय परिसर में एक दिवसीय वृहद रोजगार मेला का सकुशल आयोजन किया गया। सहायक निदेशक सेवायोजन चन्द्र कान्त सिंह ने बताया कि उक्त मेले में 16 प्रतिष्ठित कंपनियों ने विभिन्न पदों पर भर्ती करने हेतु आई थी, जिसमें लगभग 250 अभ्यर्थियो ने प्रतिभाग किया।

इस रोजगार मेले में मुख्य अतिथि विधायक रुधौली राजेंद्र प्रसाद चौधरी एवं विशिष्ट अतिथि विद्यालय प्रबंधक पंकज पटेल, जिला सेवायोजन अधिकारी अवधेन्द्र प्रताप वर्मा व सहायक सेवायोजन अधिकारी श्रीमती अंजलि शर्मा ने सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

विधायक रुधौली ने अपने उद्बोधन में कहा कि युवाओं को बेहतर रोजगार दिलाने के उद्देश्य में यह वृहद रोजगार मेला आयोजित किया गया है। उन्होंने सेवायोजन कार्यालय के अधिकारियों को आयोजन करने हेतु सराहना की व उपस्थित प्रतिभागी अभ्यर्थियों को उनके बेहतर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं की। उन्होंने अभ्यर्थियो को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बहुत ही अच्छा मौका है कि जब अभ्यर्थी अपने ही क्षेत्र में साक्षात्कार के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।

विशिष्ट अतिथि ने उपस्थित अभ्यार्थियों को शुभकामनाएं दी व आयोजक मंडल को बधाई दी। जिला सेवायोजन अधिकारी अवधेन्द्र प्रताप वर्मा ने प्रतिभागी अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह मेला पूरी तरह से निःशुल्क है अभ्यर्थीगण अपने शैक्षिक योग्यता के अनुसार अलग–अलग कंपनियों के आवंटित कक्ष में अपने–अपने बायोडाटा के साथ इंटरव्यू के माध्यम से चयन हेतु प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके उपरांत माननीय अतिथिगणों द्वारा रोजगार मेला में विभिन्न कंपनियों में चयनित लगभग 09 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र/ऑफर लेटर भी वितरित किया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य राकेश कुमार शर्मा अंत में सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

कार्यक्रम का संचालन सहायक अध्यापक बाबू राम वर्मा ने किया। इस कार्यक्रम के आयोजन में विद्यालय की तरफ से सभी स्टाफगण और क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय बस्ती की ओर से प्रमोद कुमार प्लेसमेंट इंचार्ज, पंकज कुमार श्रीवास्तव, मो. वसीम खान, सतीशंकर मौर्य, राकेश राय, सुरेश कुमार आदि मौजूद रहे।

## आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी को सुप्रीमकोर्ट से राहत



नई दिल्ली (आभा)। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया है। साथ ही, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जाए, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत कानूनी रूप से विचार योग्य है या नहीं। यह मामला कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास उनकी ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में कहीं अधिक संपत्ति है। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को इन आरोपों की जांच करने और उठाए गए कदमों के बारे में कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया था।

# सपा, कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर ठनी, गठबंधन में बढा तनाव



लखनऊ (आभा)। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन सपा की उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आने के बाद गठबंधन में तनाव के संकेत मिलने लगे हैं। कांग्रेस सांसद और यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने सपा के कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि बातचीत के साथ–साथ उम्मीदवारों की घोषणा करना गठबंधन को लेकर उसकी गंभीरता पर संदेह पैदा करता है।

समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पांच उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। यह घोषणा कांग्रेस के साथ दिल्ली में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत के कुछ घंटे बाद हुई। इस दौरान सपा ने कांग्रेस को शुरुआती प्रस्ताव के तौर पर 403 सीटों में से 26 सीटें देने की बात कही थी।

इमरान मसूद ने कहा कि एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है, वहीं दूसरी ओर चुनावी घोषणाएं भी कर रही है। उन्होंने इसे गठबंधन की मंशा को लेकर सवाल खड़े करने वाला कदम बताया। मसूद ने कहा, "जो कुछ यहां हो रहा है, उससे लगता है कि इस मामले में गंभीरता की कमी है। एक तरफ आप (समाजवादी पार्टी) बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ घोषणाएं कर रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।"

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कहते हैं, 'उनको अच्छी नहीं लगती बुलंदी मेरी, उनको शायद मेरी परवाज बहुत खलती है' – बस यही जवाब है... कांग्रेस जब चाहेगी अपने उम्मीदवार उतारेगीय इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आप गठबंधन के बीच ऐसा बर्ताव करते हैं, तो फिर यह गठबंधन नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी तरफ से कोई गंभीरता नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 181 विधानसभा सीटों की मांग की थी, जबकि सपा की ओर से शुरुआती प्रस्ताव में 26 सीटें देने की बात सामने आई। हालांकि, सीटों की मांग और प्रस्ताव से जुड़ी सूची की दोनों पक्षों ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। कांग्रेस पहले ही सहारनपुर जिले की सीटों पर उम्मीदवार चयन में अपनी भूमिका की मांग कर चुकी थी। इमरान मसूद सहारनपुर से सांसद हैं। सपा की उम्मीदवारों की घोषणा पर नाराजगी जताते हुए इमरान मसूद ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पार्टी कांग्रेस से मुकाबला करना चाहती है या भाजपा से। मसूद ने कहा कि इस स्थिति में कांग्रेस के भीतर चर्चा की जाएगी कि आगे क्या करना है और सपा के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति पार्टी तय करेगी। समाजवादी पार्टी की ओर से इमरान मसूद के बयान पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।

## मतदाता सूची पुनरीक्षण में निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग




–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2027 कार्यक्रम को प्रभावी एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्रीमती कृतिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।

बैठक में जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने–अपने सभी पोलिंग स्टेशनों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की तैनाती सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में राजनैतिक दलों की सहभागिता महत्वपूर्ण है। बीएलए की सक्रिय भागीदारी से बूथ स्तर पर पात्र मतदाताओं की पहचान तथा मतदाता सूची को अद्यतन बनाने में मदद मिलेगी।

जिलाधिकारी ने प्रतिनिधियों से नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फार्म–6 भरवाने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं सहित सभी पात्र नागरिकों को मतदाता बनने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।

उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से पुनरीक्षण अभियान को जनभागीदारी के साथ सफल बनाने, बूथ स्तर पर समन्वय स्थापित करने तथा मतदाता पंजीकरण के कार्य में सक्रिय सहयोग देने की अपेक्षा की। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम सुनंद सुधाकरन, एडीओ ओम प्रकाश, वरिष्ठ सहायक पीयूष प्रधान सहायक अजय पाण्डेय, संबंधित अधिकारी तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

# संविधान दिवस पर घोषणा पत्र जारी करेगी सपा

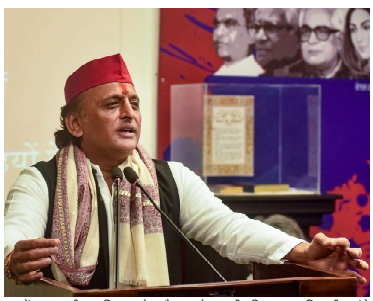

**लखनऊ (आभा)।** विधानसभा चुनावों के लिए सहयोगी दल कांग्रेस के साथ गठबंधन और सीट बंटवारे पर चल रही चर्चा और बवाल के बीच समाजवादी पार्टी ने एक और चुनावी छलांग लगाने की घोषणा की है। पार्टी 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। पार्टी ने इसे 'जन–मन घोषणा पत्र' नाम दिया है, जो तीन कैटगरी में होंगी। बताया जा रहा है कि इसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों पर फोकस तो होगा ही इसके साथ–साथ आम जनता और महिलाओं के मुद्दों पर भी विशेष फोकस रहेगा। इससे पहले पार्टी ने नई छलांग लगाते हुए मंगलवार की रात पांच उम्मीदवारों का ऐलान किया था।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा का ये चुनावी घोषणा पत्र जारी होगा। इस घोषणा पत्र को 'जन–मन घोषणा पत्र' और 'सत्ताइस का संकल्प: पीडीए का प्रण पत्र' नाम दिया गया है। इसे तीन कैटगरी में बनाया गया है। पहली कैटगरी राज्य स्तरीय होगी, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए चुनावी वादे किए जाएंगे। इसमें राज्य की प्रगति का रोड मैप पेश किया जाएगा।

दूसरे स्तर का घोषणा पत्र जिला स्तरीय होगा। यानी राज्य के सभी 75 जिलों के लिए उनकी स्थानीय समस्याओं और विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चुनावी वादों का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जबकि तीसरे स्तर पर राजधानी लखनऊ को विशेष तौर पर फोकस करते हुए एक अलग घोषणा पत्र तैयार किया गया है। इसमें लखनऊ के शहरी विकास, बुनियादी ढांचे और स्थानीय मुद्दों को संबोधित करते हुए चुनावी वादे किए जाएंगे।

सूत्रों ने बताया कि लखनऊ के तैयार घोषणा पत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या को बड़ी जगह देते हुए राजधानी को जाम से मुक्ति करने की कार्ययोजना को जगह दी गई है। इसके तहत फ्लाईओवर और चमकती सड़कों पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा राजधानी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा पर भी जोर देने की बात कही जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इस चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को खास तवज्जो देने की तैयारी की गई है। समाजवादी पार्टी उन्हें सालाना 40,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान घोषमा पत्र में कर सकती है। हालांकि, इस स्कीम के तहत कौन पात्र होगा, इसकी जानकारी अभी इसमें नहीं दी जाएगी। महिलाओं के साथ–साथ युवाओं पर भी चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए जाने की उम्मीद है।सपा का ये घोषणा पत्र ऐसे समय में जारी होने जा रहा है, जब गठबंधन के साथी दल कांग्रेस के साथ खींचतान मची हुई है। सीट शेयरिंग पर चर्चा के बीच ही सपा ने मंगलवार की रात पांच उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इससे दोनों दलों के बीच खींचतान चरम पर है। सपा के इस कदम पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस की राज्य कार्यसमिति के प्रमुख इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, श्श्हम भीख नहीं मांग रहे हैं।श्श मसूद इस बात से खासे नाराज हैं कि जिन पांच सीट पर सपा ने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, उनमें सहारनपुर भी शामिल है, जो उनका लोकसभा क्षेत्र है।

## बसपा की बैठक में बनी विधानसभा चुनाव की रणनीतिः 6 दिसम्बर को लखनऊ पहुंचेंगे कार्यकर्ता



–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बुधवार को बहुजन समाज पार्टी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक जिलाध्यक्ष जयहिन्द गौतम के संयोजन में हर्दिया चौराहे के निकट स्थित एक मैरेज हाल के समागार में सम्पन्न हुई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर रणनीति बनाने के साथ ही बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसम्बर को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सेदारी पर विचार किया गया।

बैठक को सम्बोधित करते हुये मुख्य अतिथि मुख्य मण्डल प्रभारी मदनराम ने कहा कि बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिये पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता तैयारियों में पूरी ताकत से जुट जाय और बूथ स्तर के मतदाता सूची की समीक्षा कर ले। कहा कि बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसम्बर को लखनऊ में डा. भीमराव अम्बेडकर पार्क बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी ताकत का अहसास कराये।

अध्यक्षता करते हुये मुख्य मण्डल प्रभारी इन्दलराम ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार से ऊब चुकी है और सर्व समाज मिलकर बसपा की मजबूत सरकार बनाने की इच्छुक हैं। ऐसे में बसपा पदाधिकारी पूरी ताकत झोंक दें। रूहौली विधानसभा प्रभारी और प्रत्याशी मो. खालिक उर्फ वीरेन्द्र ने कहा कि रूधौली विधानसभा से हजारों की संख्या में लोग 6 दिसम्बर को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सेदारी करेंगे। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है।

बसपा जिलाध्यक्ष जयहिन्द गौतम ने कहा कि 6 दिसम्बर को लखनऊ में डा. भीमराव अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बस्ती के सभी पांचों विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे।

बैठक में मुख्य रूप से धर्मदेव, राम सूरत चौधरी, के.के. गौतम, कल्पनाथ बाबू, रामचेत निराला, राजेन्द्र प्रसाद गौतम, अजय कुमार पाण्डेय, दीपक कुमार, राना अम्बेडकर, अलीम अहमद, अतर सिंह गौतम, बच्चूलाल गौतम, राजूराव, महेन्द्र कुमार, प्रमोद कुमार, रामशंकर आजाद, बब्लू पाल, योगेन्द्र चौधरी, श्याम भवन, नवमी प्रसाद, देशराज गौतम, शैलेन्द्र गौतम, विकास कुमार राव, प्रदीप कुमार गौतम, लालमन, रामनवल, हरिनन्दन पाण्डेय, महेन्द्र कुमार, रामफेर गौतम, अजय कुमार के साथ ही बसपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

## –बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसम्बर को लखनऊ में होगी जुटान

*"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स*

दैनिक
# भारतीय बस्ती
बस्ती 26 नवम्बर 2026 गुरूवार

## सम्पादकीय

## सत्ता के लिये सियासी गठबंधन

एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों को यह तय करने का अधिकार है कि वे चुनाव के मैदान में उतरने के लिए अपना मोर्चा कैसे तैयार करते हैं और किस पक्ष में खड़े होते हैं। मगर इसी लोकतंत्र की गरिमा यह जिम्मेदारी भी तय करती है कि आम जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ न किया जाए। सवाल है कि देश की राजनीति में इस तकाजे का खयाल रखने की कसौटी पर कितने राजनीतिक दल खरे उतर पाते हैं और कितनों को इस बात की फिक्र करने की जरूरत महसूस होती है कि आम जनता उसके रुख के बारे में क्या सोचेगी।

पंजाब की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच फिर से चुनावी साझेदारी की घोषणा कोई हैरान करने वाली घटना नहीं है। इससे पहले भी भाजपा–शिअद गठबंधन में साथ रहकर सरकार भी बना चुके हैं। मगर विचारधारात्मक रूप से एक–दूसरे से भिन्न मोर्चे पर होने और जनता से जुड़े मुद्दों पर संबंध टूटने के बाद अगर सत्ता हासिल करने की होड़ में फिर से एक–दूसरे के साथ आने की जरूरत पड़ रही हो, तो यह जितना लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुविधा है, उससे ज्यादा इसे अवसर की राजनीति के तौर पर देखा जाएगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के मसले पर किसानों के बीच उभरे व्यापक विरोध के बाद शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन सितंबर 2020 में टूट गया था। तब भाजपा की सरकार पर किसानों के हितों को नजरअंदाज करने के आरोप के साथ शिअद सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

पंजाब में आज भी किसान केंद्र सरकार की नीतियों को कठघरे में खड़ा करते हैं। ऐसे में शिअद और भाजपा के साथ आने की घोषणा के समय को लेकर स्वाभाविक ही सवाल उठ रहे हैं। राज्य में मजबूत उपस्थिति रखने वाले दलों के बीच छह सालों के अलगाव के बाद शिअद और भाजपा के फिर साथ आने को कोई सकारात्मक लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, बल्कि अवसरवाद और सत्ता की भूख में बिना जवाबदेही के पुनर्मिलन के तौर पर देखा जा रहा है। अब यह देखने की बात होगी कि जिन मुद्दों पर शिअद ने भाजपा से दूरी बनाई थी, उस पर जनता की ओर से उठे सवालों पर उसका क्या रुख होता है।

ऐसे उदाहरण अक्सर सामने आते रहते हैं, जिसमें सत्ता की सियासत में आम जनता की भावनाओं और विचार को दरकिनार कर पार्टियां सुविधा के हिसाब से अपना पक्ष तय कर लेती हैं। ऐसे में होता यही है कि अगर किसी खास पार्टी को जनता ने उसकी विचारधारा के आधार पर समर्थन दिया होता है, तो अगले कुछ समय में वह पार्टी अपने विचारों के उलट किसी खेमे में दिखाई देती है।

जनता के सामने सत्ता के ढांचे में अपनी लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव में वोट डालना एक अहम विकल्प होता है। राजनीतिक दल इसी को लोगों की मजबूरी समझते हैं और भावनात्मक मुद्दों को हवा देकर इसका इस्तेमाल अपने हक में करने से नहीं हिचकते। पंजाब में शिअद और भाजपा के साथ आने को भले ही चुनावी राजनीति की व्यावहारिक वास्तविकता बता कर उचित ठहराने की कोशिश की जाए, लेकिन सच यही है कि विधानसभा या लोकसभा चुनाव के ऐन पहले सत्ता हासिल करने के लिए अपनी विचारधारा और नैतिकता को दरकिनार कर ऐसे गठबंधन बनते हैं, तो उसमें जनता के भरोसे की जगह कमजोर होती है।

## जहरीली शराब से मौतें

देश के किसी भी इलाके में शराब बिक्री की व्यवस्था को नियमित और नियंत्रित तरीके से चलाने के दावे करने में सरकार की ओर से कोई कमी नहीं की जाती, लेकिन इसकी हकीकत अक्सर सामने आती है, जब जहरीली शराब के सेवन की वजह से लोगों के मरने की खबरें आती हैं।

किसी भी जगह पर इस तरह की घटना का सबक यह होना चाहिए कि इससे संबंधित नियम–कायदों और निगरानी को पूरी तरह दुरुस्त किया जाए, ताकि वैसा फिर न हो। मगर अमूमन हर जगह लापरवाही का आलम ऐसा होता है कि जहरीली शराब पीकर मौत के मामलों का सिलसिला–सा चलता रहता है और सरकार हर बार रस्म की तरह घटना की जांच और कार्रवाई का आश्वासन देने में कोई कमी नहीं करती। इसके बाद अगली घटना यह बताती है कि सरकारी तंत्र को नाहक ही लोगों के मारे जाने से क्या फर्क पड़ता है। गौरतलब है कि मणिपुर में जहरीली शराब पीकर कम से कम सोलह लोगों की मौत हो गई और कई सौ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन शासन की सफाई है कि शराब जिले के बाहर के किसी इलाके से लाई गई थी। सवाल है कि क्या इस तरह की सफाई से समस्या का समाधान हो जाता है!

विडंबना यह है कि जब जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या ज्यादा होने लगती है और मामला तूल पकड़ने लगता है, तब स्थानीय प्रशासन सभी स्तर पर सक्रिय दिखने लगता है। पीड़ितों का इलाज कराने से लेकर आरोपियों की धर–पकड़ के लिए जिस तरह अभियान चलाए जाते हैं, वह आम दिनों में नदारद होता है।

शराब की बिक्री के संबंध में तय सभी नियम–कायदे या गुणवत्ता पर निगरानी को लेकर संबंधित महकमे एक तरह से आंखें मूंदे रहते हैं। यह बेवजह नहीं है कि इस लापरवाही का फायदा उठाकर अपराधी प्रवृत्ति के लोग जहरीली शराब की आपूर्ति करने में कामयाब हो जाते हैं। मणिपुर पहले ही सामुदायिक टकराव की समस्या से जूझ रहा है और सरकार प्रकारांतर से इस समस्या के समाधान में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में जहरीली शराब से हुई मौतें मणिपुर के लिए दोहरी चिंता का मसला है। अगर सरकारी तंत्र और संबंधित महकमे अपनी ड्यूटी को लेकर ईमानदार तथा सजग रहें, तो ऐसी त्रासदियों से बचा जा सकता है।

# भारत और पाकिस्तान में प्रिवी पर्स के खात्मे की दिलचस्प कहानी






–अखिल कुमार यादव–

भारत की आजादी केवल अंग्रेजी शासन के अंत की घटना नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसे विशाल भूभाग को राजनीतिक रूप से एकजुट करने की चुनौती भी थी, जहां सैकड़ों देशी रियासतें, अलग–अलग शासक और अपनी–अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं मौजूद थीं। ब्रिटिश भारत के साथ–साथ देश में अनेक ऐसी रियासतें थीं, जिनके राजा, नवाब और महाराजा अपने क्षेत्रों में शासन करते थे। आजादी के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि इन रियासतों को नवगठित भारत और पाकिस्तान का हिस्सा किस तरह बनाया जाए। इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया में एक व्यवस्था सामने आई, जिसे 'प्रिवी पर्स' कहा गया। प्रिवी पर्स की कहानी केवल राजाओं को दिए जाने वाले भत्ते की कहानी नहीं है। यह सत्ता के हस्तांतरण, राजनीतिक समझौतों, राष्ट्रीय एकीकरण, लोकतांत्रिक मूल्यों और बदलते समय के साथ राजशाही के विशेषाधिकारों के अंत की कहानी भी है। दिलचस्प बात यह है कि भारत और पाकिस्तान, दोनों ने अपने यहां रियासतों के शासकों के लिए प्रिवी पर्स की व्यवस्था अपनाई, लेकिन बाद में दोनों देशों ने इसे समाप्त करने के अलग–अलग रास्ते चुने।

'प्रिवी पर्स' अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है। 'प्रिवी' का अर्थ निजी और 'पर्स' का अर्थ धन की थैली या कोष है। ब्रिटिश राजपरंपरा में 'प्रिवी पर्स' का संबंध सम्राट अथवा राजपरिवार के निजी खर्चों के लिए निर्धारित धन से भी रहा है। हालांकि भारत में आजादी के बाद जिस व्यवस्था को प्रिवी पर्स कहा गया, उसका स्वरूप अलग था। यहां यह किसी राजा के निजी खर्च के लिए सामान्य सरकारी अनुदान नहीं, बल्कि अपनी रियासत की संप्रभु सत्ता और शासनाधिकार छोड़कर भारतीय संघ में शामिल होने वाले पूर्व शासकों के साथ किया गया एक राजनीतिक एवं संवैधानिक समझौता था। दरअसल, 15 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने के साथ ही देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता यानी पैरामाउंटसी का अंत हो गया। उस समय देश में सैकड़ों रियासतें थीं। ब्रिटिश भारत के प्रांत सीधे अंग्रेजी शासन के अधीन थे, जबकि देशी रियासतों में स्थानीय शासकों का शासन चलता था। स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों के सामने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने अथवा अलग रहने का विकल्प जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। यदि सभी रियासतें स्वतंत्र रहने का रास्ता चुनतीं तो भारतीय उपमहाद्वीप छोटे–छोटे राजनीतिक क्षेत्रों में बंट सकता था। इससे राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा, संचार, व्यापार और प्रशासन के सामने गंभीर संकट खड़ा हो सकता था। इस चुनौती को समझते हुए तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल और उनके सहयोगी वी.पी. मेनन ने रियासतों के एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भी शासकों को भारत में शामिल होने के लिए राजी करने में सहयोग किया। इस प्रक्रिया में केवल भावनात्मक अपील पर्याप्त नहीं थी। रियासतों के शासकों को यह भरोसा देना जरूरी था कि सत्ता छोड़ने के बाद उनके व्यक्तिगत जीवन और आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार अपने वादों का सम्मान करेगी। इसी उद्देश्य से प्रिवी पर्स की व्यवस्था को विलय समझौतों और संविदाओं का हिस्सा बनाया गया।

यह कहना उचित नहीं होगा कि प्रिवी पर्स का विचार किसी एक व्यक्ति ने अचानक प्रस्तुत किया था। इसके पीछे ब्रिटिश काल की कुछ पुरानी व्यवस्थाओं, रियासतों से संबंधित वार्ताओं और स्वतंत्रता के आसपास तैयार किए गए विभिन्न प्रस्तावों का अनुभव था। वी.पी. मेनन ने रियासतों के एकीकरण के व्यावहारिक पक्ष को समझते हुए इस तरह के आर्थिक आश्वासन को वार्ता का हिस्सा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल ने इसे राजनीतिक स्तर पर समर्थन दिया और शासकों के साथ हुए समझौतों को राष्ट्रीय एकीकरण के व्यापक लक्ष्य से जोड़ा। 12 अक्टूबर, 1949 को संविधान सभा में सरदार पटेल ने प्रिवी पर्स के औचित्य पर विस्तार से अपनी बात रखी थी। उनका तर्क था कि शासकों के पास अपनी रियासतों का अलग अस्तित्व बनाए रखने की स्थिति थी और उन्हें अपनी शासन–सत्ता छोड़ने के लिए राजी करना आसान नहीं था। ऐसे में प्रिवी पर्स और कुछ विशेषाधिकार सत्ता छोड़ने के बदले दिया गया प्रतिफल थे। उन्होंने इसे देश के व्यापक हित में शांतिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन की कीमत के रूप में प्रस्तुत किया। संविधान सभा में उनके वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि सरकार इस व्यवस्था को केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि रियासतों के विलय से जुड़े ऐतिहासिक समझौते का हिस्सा मानती थी। प्रिवी पर्स की राशि सभी रियासतों के लिए समान नहीं थी। इसका निर्धारण रियासत की आय, आकार और विलय समझौते की शर्तों के आधार पर किया गया। सरदार पटेल ने संविधान सभा में बताया था कि सामान्य गणना में रियासत की औसत वार्षिक आय के पहले एक लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, अगले चार लाख रुपये पर 10 प्रतिशत और पांच लाख रुपये से ऊपर की आय पर 7.5 प्रतिशत के आधार का उपयोग किया गया था। कुछ बड़ी रियासतों के मामलों में निर्धारित सीमा से अधिक राशि भी तय हुई। उस समय कुल वार्षिक प्रिवी पर्स दायित्व लगभग साढ़े चार करोड़ रुपये बताया गया था। यह राशि पूर्व शासकों और उनके परिवारों के निर्धारित निजी खर्चों के लिए थीय इसे सामान्य सरकारी पेंशन समझना सही नहीं होगा।

भारत में रियासतों का एकीकरण कई चरणों में हुआ। कुछ रियासतें सीधे पड़ोसी प्रांतों में मिला दी गईं, कुछ को केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के रूप में लिया गया और कई रियासतों को मिलाकर नए संघीय प्रशासनिक क्षेत्र बनाए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 के रघुनाथराव गणपतराव बनाम भारत संघ मामले में एकीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए बताया कि 216 रियासतों का प्रांतों में विलय हुआ, 61 को केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के रूप में लिया गया और 275 रियासतों को संघों में एकीकृत किया गया। इस प्रकार कुल 552 रियासतें एकीकरण योजनाओं से प्रभावित हुईं। इसलिए 552 का आंकड़ा इस न्यायिक विवरण में एकीकरण से प्रभावित रियासतों की संख्या के रूप में आता है। इस प्रक्रिया में हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू–कश्मीर जैसी रियासतों के मामले विशेष रूप से जटिल रहे। सभी रियासतों का विलय एक जैसी परिस्थितियों में नहीं हुआ। कहीं बातचीत और समझौते से रास्ता निकला तो कहीं राजनीतिक तनाव, जनमत, सैन्य कार्रवाई और सुरक्षा संबंधी परिस्थितियां निर्णायक बनीं। इसीलिए भारतीय एकीकरण को केवल प्रिवी पर्स के माध्यम से समझना अधूरा होगाय यह कूटनीति, प्रशासनिक पुनर्गठन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक व्यापक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी।

पाकिस्तान में भी रियासतों के शासकों के साथ प्रिवी पर्स की व्यवस्था अपनाई गई। हालांकि भारत और पाकिस्तान में रियासतों की संख्या तथा उनके एकीकरण की परिस्थितियां अलग थीं। पाकिस्तान के संदर्भ में अक्सर 13 रियासतों का उल्लेख किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों में वास्तविक रूप से पाकिस्तान में शामिल हुई रियासतों की सूची और भारत के जूनागढ़ तथा मनावदर जैसे मामलों को अलग–अलग समझना जरूरी है। पाकिस्तान के संघीय मंत्रालय सैफरॉन की वर्ष पुस्तिका में 12 ऐसी रियासतों का उल्लेख है, जिन्होंने पाकिस्तान से विलय किया था। इनमें बहावलपुर, खैरपुर, अंब, चितराल, दिर, स्वात, कलात, खरान, लासबेला, मकरान, हुंजा और नगर शामिल हैं। जूनागढ़ और मनावदर के शासकों द्वारा पाकिस्तान के पक्ष में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाने का उल्लेख अलग से है, लेकिन ये क्षेत्र पाकिस्तान में वास्तविक रूप से शामिल नहीं हो सके। इसीलिए पाकिस्तान की रियासतों की संख्या बताते समय 12 वास्तविक रूप से शामिल रियासतों और जूनागढ़–मनावदर के अलग दावे के बीच अंतर स्पष्ट करना चाहिए। इन रियासतों का भौगोलिक विस्तार भी उल्लेखनीय था। बहावलपुर वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में, खैरपुर सिंध में, कलात, खरान, लासबेला और मकरान बलूचिस्तान क्षेत्र में तथा अंब, चितराल, दिर और स्वात उत्तर–पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में स्थित थे। हुंजा और नगर वर्तमान गिलगित–बाल्टिस्तान क्षेत्र से संबंधित थे। यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पाकिस्तान में शामिल हुई इन रियासतों में से कोई भी वर्तमान बांग्लादेश यानी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित नहीं थी। 1947 में पूर्वी पाकिस्तान का भूगोल मुख्यतः पूर्वी बंगाल के उस क्षेत्र से बना था, जो ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत का हिस्सा था। वहां पश्चिमी पाकिस्तान की तरह अलग–अलग देशी रियासतों के विलय की वैसी प्रक्रिया नहीं हुई। इसलिए यह मानना गलत होगा कि पाकिस्तान की 12 या प्रचलित गणना में बताई जाने वाली 13 रियासतों में कोई रियासत आज के बांग्लादेश में भी थी। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच हजारों किलोमीटर की भारतीय भूमि थी, लेकिन दोनों को एक देश के रूप में जोड़ा गया था। वर्ष 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के साथ यह राजनीतिक संरचना भी समाप्त हो गई।

भारत और पाकिस्तान दोनों ने शुरुआत में पूर्व शासकों को प्रिवी पर्स देने की व्यवस्था स्वीकार की, लेकिन बाद के वर्षों में दोनों देशों ने इस पर अलग–अलग निर्णय लिए। भारत में समय के साथ यह बहस तेज हुई कि लोकतांत्रिक गणराज्य में पूर्व राजाओं को विशेष आर्थिक सुविधाएं और संवैधानिक मान्यता क्यों मिलनी चाहिए। एक ओर यह तर्क था कि प्रिवी पर्स ऐतिहासिक समझौतों का सम्मान था, वहीं दूसरी ओर यह सवाल उठ रहा था कि समान नागरिकता और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन्म या वंश के आधार पर किसी वर्ग को विशेष अधिकार देना कितना उचित है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रिवी पर्स समाप्त करने का प्रयास किया। 1970 में इससे संबंधित संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा से पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में आवश्यक बहुमत नहीं मिल सका। इसके बाद 1971 में 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रिवी पर्स समाप्त कर दिए गए। संविधान के अनुच्छेद 291 और 362 को हटाया गया तथा अनुच्छेद 363। जोड़ा गया। इसके साथ ही पूर्व शासकों की मान्यता और उनसे जुड़े विशेषाधिकार समाप्त हो गए। यह फैसला भारतीय लोकतंत्र में समानता और गणराज्य की अवधारणा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।

पाकिस्तान ने भी प्रिवी पर्स और शासकों के विशेषाधिकार समाप्त किए, लेकिन वहां यह प्रक्रिया 1972 में राष्ट्रपति आदेश संख्या 15 के माध्यम से पूरी हुई। इसका नाम (Rulers of Acceding States ¼Abolition of Privy Purses and Privileges Order 1972) था। इस आदेश ने शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त किए, लेकिन साथ ही कुछ पूर्व शासकों और उनके आश्रितों के लिए जीवनकाल तक रखरखाव भत्ता यानी मेंटेनेंस अलाउंस देने का प्रावधान भी रखा। पाकिस्तान की संसद के आधिकारिक रिकॉर्ड में 5 फरवरी, 1974 को पूर्व रियासतों के शासकों को दिए जाने वाले वार्षिक रखरखाव भत्ते का विवरण दर्ज है। इसके अनुसार बहावलपुर के पूर्व अमीर को 16 लाख रुपये, खैरपुर के पूर्व मीर को 10 लाख रुपये, कलात के पूर्व खान को 6.50 लाख रुपये, स्वात के पूर्व वाली को 9.50 लाख रुपये और दिर के पूर्व नवाब को 3.75 लाख रुपये सालाना दिए जाने का उल्लेख है। इसी रिकॉर्ड में लासबेला, मकरान, खरान और चितराल के पूर्व शासकों के लिए भी अलग–अलग रकम दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान में प्रिवी पर्स समाप्त किए जाने के बाद भी कुछ पूर्व शासकों और उनके आश्रितों को रखरखाव भत्ते मिलते रहे। इस व्यवस्था का एक और रोचक पहलू यह है कि पाकिस्तान में दशकों बाद भी पूर्व शासकों और उनके आश्रितों के लिए रखरखाव भत्ते का प्रावधान पूरी तरह अप्रासंगिक नहीं हुआ। पाकिस्तान के आधिकारिक दस्तावेजों में वर्ष 2021–22 के दौरान पूर्व रियासतों के शासकों और आश्रितों को कुल 4.2 करोड़ रुपये के रखरखाव भत्ते दिए जाने का उल्लेख मिलता है। यह आंकड़ा बताता है कि दोनों देशों में राजशाही के औपचारिक विशेषाधिकार समाप्त होने के बाद भी उनके साथ किए गए पुराने समझौतों के कुछ वित्तीय प्रभाव लंबे समय तक बने रहे।

प्रिवी पर्स के इतिहास को देखते हुए यह समझना जरूरी है कि भारत में इसका गठन और अंत, दोनों अपने–अपने समय की राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़े थे। आजादी के तत्काल बाद देश के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक स्थिरता थी। उस समय पूर्व शासकों को आर्थिक आश्वासन देना एक व्यावहारिक समझौता था, जिसके माध्यम से सत्ता का हस्तांतरण अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण ढंग से संभव हुआ। लेकिन जब देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हुईं और समानता का संवैधानिक आदर्श अधिक महत्वपूर्ण बना, तब वंशानुगत विशेषाधिकारों को समाप्त करने की मांग भी स्वाभाविक रूप से सामने आई।

इस तरह प्रिवी पर्स की कहानी एक ऐतिहासिक विरोधाभास भी सामने रखती है। जिस व्यवस्था को कभी देश के एकीकरण और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण का साधन बनाया गया था, उसी व्यवस्था को बाद में लोकतांत्रिक समानता के सिद्धांत के आधार पर समाप्त कर दिया गया। यही लोकतंत्र की विशेषता है कि वह परिस्थितियों के अनुसार अपने निर्णयों और व्यवस्थाओं की समीक्षा करता है। भारत के लिए प्रिवी पर्स केवल राजाओं को दिया गया धन नहीं था, बल्कि वह एक ऐसे दौर का राजनीतिक समझौता था, जिसने सैकड़ों रियासतों को एक राष्ट्र में समाहित करने में भूमिका निभाई। और उसका अंत इस बात का प्रतीक बना कि स्वतंत्र भारत में अंतिम संप्रभुता किसी राजा या राजपरिवार की नहीं, बल्कि जनता की है।

# चुनावी महासंग्राम की राह पर यूपी

–निर्मल रानी–



उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सदस्यों के लिये होने वाले आम चुनाव, फरवरी–मार्च 2027 में होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के 4 अन्य राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी संभवतः फरवरी–मार्च 2027 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इन सभी पाँचों राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च से मई 2027 के बीच समाप्त हो रहा है। इन पांच राज्यों के अलावा, वर्ष 2027 के अंत यानी नवंबर/दिसंबर में दो अन्य राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव निर्धारित हैं। इन विधान सभा चुनावों को 2029 के प्रस्तावित लोकसभा चुनावों के सेमी फाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। वैसे तो इन सभी पांचों राज्यों में चुनाव बेहद दिलचस्प होने की संभावना है परन्तु सबसे चुनौतीपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार अपनी चुनावी बिसात बिछाने वाला देश का यह सबसे बड़ा प्रदेश इस बार न केवल साम्प्रदायिक बल्कि जातीय समीकरणों में भी बुरी तरह उलझ चुका है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एस आई आर के बाद, निर्वाचन आयोग ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है और नाम जोड़ने व सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 17 नवंबर 2026 को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश में कुल 13.58 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए हैं। 10 अप्रैल 2026 को एसआईआर के बाद प्रकाशित अंतिम सूची की तुलना में इस मसौदा सूची में 18,84,113 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में महिला मतदाताओं की संख्या में 10,96,828 और पुरुष मतदाताओं की संख्या में 7,87,449 का इजाफा हुआ है। इससे पहले एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 15.44 करोड़ मतदाताओं की जांच के बाद 12.55 करोड़ नाम बरकरार रखे गए थे और लगभग 2.89 करोड़ नाम सूची से हटाए गए थे। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि पंचायत और विधानसभा मतदाता सूची के भ्रम के कारण 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम सूची में नहीं जुड़ पाए हैं। इसके मद्देनजर भाजपा ने हर बूथ पर मतदाता जोड़ने के लिए एक महीने का विशेष अभियान शुरू किया है। इसी तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने भी मतदाता सूची में संभावित गड़बड़ियों और नाम कटने के मुद्दों पर सवाल उठाए हैं और अपने कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची की निगरानी के लिए सक्रिय किया है। उधर मुस्लिम समाज भी न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जानबूझ कर पूर्व नियोजित तरीके से एक बड़ी साजिश के तहत मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटे जाने की शिकायत कर रहा है। उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में जहां भाजपा बनाम इण्डिया गठबंधन (कांग्रेससमाजवादी पार्टी ) चुनावी मुकाबला होने की संभावना थी वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी शुरू से ही अपनी डफली अलग ही बजा रही है। कुछ राजनैतिक विश्लेषक इसे मायावती द्वारा भाजपा को लाभ पहुँचाने की कोशिश की नजर से भी देख रहे हैं। परन्तु पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी की ए आई एम एम ने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से लोकसभा सांसद और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) से चुनाव पूर्व समझौता कर उत्तर प्रदेश के राजनैतिक हल्कों में खलबली पैदा कर दी है। बसपा जैसे दलों की सक्रियता से मुस्लिम वोटों के बंटवारे की संभावना पर जहां पहले भी चर्चा होती रही है वहीं चुनाव नजदीक आने पर बने ओवैसी चंद्रशेखर के यह नये समीकरण व इसके द्वारा उठाये जाने वाले धर्मस्थल विध्वंस,लक्षित एस आई आर,अवैध घुसपैठ, धर्मांतरण, धार्मिक जुलूसों जैसे अनेक ऐतिहासिक विवादों पर तीखे बयान सामाजिक और साम्प्रदायिक संवेदनशीलता को और भी बढ़ा रहे हैं। गोया उत्तर प्रदेश के लगभग 19द्ध 20: मुस्लिम मतदाताओं के रुझान को लेकर एक ओर जहां सपा–कांग्रेस गठबंधन इस वोट बैंक को एकजुट रखने का प्रयास कर रहे थे वहीं असदुद्दीन ओवैसी के ए आई एम एम व चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और बसपा जैसे दलों की सक्रियता से मुस्लिम वोटों के बंटवारे की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है।

# विवाह और दहेज की सौदेबाजी

– डॉ. सत्यवान सौरभ–



भारतीय समाज में विवाह को दो व्यक्तियों के बीच जीवनभर के साथ, विश्वास और जिम्मेदारियों का संबंध माना गया है। लेकिन बदलते सामाजिक परिवेश में विवाह की पवित्रता पर बाजारवाद की ऐसी छाया पड़ी है कि रिश्तों का मूल्यांकन अब व्यक्ति के संस्कार, विचार, व्यवहार और मानवीय गुणों से अधिक उसकी नौकरी, वेतन, पद और आर्थिक हैसियत से होने लगा है। विवाह के लिए लड़के की तलाश करते समय लड़की पक्ष की पहली प्राथमिकताओं में सरकारी नौकरी, अच्छा वेतन, अपना मकान, जमीन–जायदाद और सामाजिक प्रतिष्ठा शामिल हो जाती हैं। सरकारी नौकरी वाला दामाद मिल जाए तो परिवार स्वयं को भाग्यशाली समझता है। लेकिन इसी मानसिकता के भीतर एक ऐसा विरोधाभास छिपा है, जिस पर समाज खुलकर चर्चा करने से बचता है। यदि लड़की पक्ष सरकारी नौकरी वाले दामाद को प्राथमिकता देता है और लड़के वाला पक्ष बदले में ब्रेजा, ऑडी या महँगी गाड़ी की माँग रख देता है, तो क्या इसे केवल उसकी व्यक्तिगत पसंद कहकर स्वीकार कर लिया जाना चाहिए? क्या विवाह वास्तव में दो परिवारों का मिलन है या योग्यताओं और संपत्तियों की नीलामी का कोई मंच?

यह सवाल किसी एक परिवार, जाति, वर्ग या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह उस सामाजिक मानसिकता पर चोट करता है, जिसमें विवाह को धीरे–धीरे आर्थिक लेन–देन का माध्यम बना दिया गया है। विडंबना देखिए कि लड़की के माता–पिता अपनी बेटी के लिए सरकारी कर्मचारी दामाद इसलिए चाहते हैं कि उसका भविष्य सुरक्षित रहे, उसे आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े और समाज में उसे सम्मान मिले। उनकी यह इच्छा अपने आप में अनुचित नहीं है। प्रत्येक माता–पिता अपनी संतान के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है, जब इसी सुरक्षा की तलाश में वे लड़के की नौकरी को उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रमाणपत्र मान लेते हैं। सरकारी नौकरी मिलते ही लड़के का सामाजिक मूल्य बढ़ जाता है और विवाह के बाजार में उसकी कथित कीमत भी निर्धारित होने लगती है।

यहीं से दहेज की मानसिकता को खाद–पानी मिलता है। लड़के के परिवार को लगता है कि उनके बेटे ने प्रतियोगी परीक्षाएँ पास की हैं, वर्षों मेहनत की है, इसलिए विवाह में महँगी गाड़ी, नकदी, जमीन, फर्नीचर और अन्य सुविधाएँ माँगना उनका अधिकार है। दूसरी ओर लड़की का परिवार भी अपनी सामाजिक हैसियत और प्रतिष्ठा बचाने के लिए इन माँगों को पूरा करने की कोशिश करता है। कोई ब्रेजा को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता है तो किसी की निगाह ऑडी पर टिक जाती है। माँग पूरी न होने पर रिश्ते टूट जाते हैं और कई बार लड़की के माता–पिता अपनी आर्थिक क्षमता से बाहर जाकर कर्ज तक उठा लेते हैं। सवाल यह है कि जिस सरकारी नौकरी को बेटी के सुरक्षित भविष्य की गारंटी समझा गया था, क्या उसी नौकरी के नाम पर उसके माता–पिता को आर्थिक बोझ तले दबाना उचित है?

दहेज की समस्या को केवल लड़के वालों के लालच तक सीमित करके देखने से भी सामाजिक तस्वीर अधूरी रह जाती है। लड़की पक्ष की वह मानसिकता भी आत्मगौरव की माँग करती है, जो अच्छे संस्कारों, शिक्षा, चरित्र और पारिवारिक व्यवहार की अपेक्षा सरकारी नौकरी और आर्थिक संपन्नता को सर्वोच्च स्थान देती है। जब हम स्वयं किसी व्यक्ति को उसकी नौकरी और वेतन के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा देते हैं, तब अनजाने में उसी व्यवस्था को मजबूत करते हैं, जिसमें विवाह के नाम पर आर्थिक अपेक्षाएँ पैदा होती हैं। हालांकि इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि लड़की पक्ष की प्राथमिकता के कारण लड़के वालों की दहेज माँग जायज हो जाती है। माँग करने वाला ही अपने आचरण के लिए जिम्मेदार है। किसी की पसंद या अपेक्षा दूसरे व्यक्ति के शोषण का अधिकार नहीं बन सकती।

वास्तविकता यह भी है कि सरकारी नौकरी की चमक के पीछे कई बार व्यक्ति के वास्तविक चरित्र को देखने की कोशिश ही नहीं की जाती।

# आटो चालक को ट्रैक्टर से कुचला, मौत

**संवाददाता–महराजगंज।** भिटौली थाना क्षेत्र में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। क्षेत्र के पकड़ी दीक्षित गांव के पास ट्रैक्टर ने ऑटो में टक्कर मार दी। घटना के बाद ऑटो चालक ने ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की तो चालक ने उसके ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी। इससे ऑटो चालक की मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर भाग गया। पकड़ी दीक्षित निवासी वीरेंद्र (55) मंगलवार शाम करीब चार बजे ऑटो में सवारी बैठाकर परतावल–पुरैना मार्ग से जा रहे थे। पकड़ी दीक्षित के पास एक ट्रैक्टर ने उनके ऑटो में टक्कर मार दी। इसके बाद वीरेंद्र ने ट्रैक्टर चालक को रोकने की कोशिश की। आरोप है कि इससे नाराज चालक ने ट्रैक्टर का पहिया उनके दोनों पैरों पर चढ़ा दिया। इसके बाद वह मौके से भाग गया। इस घटना में ऑटो में बैठे अन्य लोग सुरक्षित हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा–तफरी मच गई। राहगीरों की मदद से गंभीर रूप से घायल वीरेंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान वीरेंद्र की मौत हो गई। वहां से परिजन शव लेकर सीएचसी परतावल पहुंचे। सूचना पर परतावल चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घटना के बाद गांव के लोगों में आक्रोश है। परिवार ने अभी तहरीर नहीं दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास के चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की पहचान की कोशिश की जा रही है। –अंकुर गौतम, सीओ सदर

# सरकारी योजनाओं और सुरक्षा पर शिविर, महिला–बाल सुरक्षा, हेल्पलाइन और कानूनी सहायता की जानकारी दी

**संवाददाता–महराजगंज।** ग्राम पंचायत बसवार में बुधवार को जागरूकता शिविर लगा। पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति ने 'सुरक्षित शैशव कार्यक्रम' के तहत पंचायत भवन में शिविर आयोजित किया। इसमें ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं, महिला सशक्तिकरण और बच्चों की सुरक्षा की जानकारी दी

महिला कल्याण विभाग की जेंडर स्पेशलिस्ट संजा देवी ने प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। इनमें निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, वन स्टॉप सेंटर, रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, स्पॉन्सरशिप योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मिशन वात्सल्य, शक्ति सदन, हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वुमेन, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ और दत्तक ग्रहण इकाई शामिल हैं। उन्होंने महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के इस्तेमाल की जानकारी भी दी।

थाना चौक से आए हेड कांस्टेबल अखिलेश यादव और महिला कांस्टेबल सीमा ने 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत 'हर नारी की सुरक्षा, हर नारी का अधिकार' विषय पर बात की। उन्होंने घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और महिला उत्पीड़न के मामलों में पुलिस सहायता, कानूनी सलाह, मनोवैज्ञानिक परामर्श और आत्मरक्षा प्रशिक्षण की जानकारी दी। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा पर भी बात की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पैरालीगल वालंटियर्स पूर्णिमा गौतम और खुशी राव ने निशुल्क कानूनी सहायता, लोक अदालत और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की जानकारी दी। पंचायत मित्र जोखन प्रसाद ने ग्राम विकास योजनाओं और स्व–जनगणना का महत्व बताया। पंचायत सहायक विपिन तिवारी ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समझाई।

समिति के श्रवण कुमार ने बाल श्रम, बाल विवाह और बाल तस्करी रोकने के लिए 'गुड पेरेंटिंग' पर जोर दिया। आनंद कुमार ने साइबर अपराधों से बचाव के तरीके बताए। कार्यक्रम का समापन कृष्ण मोहन के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

# किन्नर रूबी ने घुड़दौड़ में लहराया परचम, देशभर में दूसरे स्थान पर रहा 'शेरा'

**संवाददाता–कुशीनगर।** सामाजिक रूढ़ियों और सीमाओं से आगे बढ़कर अपनी मेहनत, लगन और हौसले से पहचान बनाने वाली किन्नर समाज की रूबी नायक ने एक बार फिर कुशीनगर का नाम रोशन किया है। फाजिलनगर के रहसू जनूबी पट्टी गांव की रूबी नायक के घोड़े शेरा ने महाराष्ट्र के परभणी में आयोजित देशस्तरीय घुड़चाल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया।



बुधवार को गांव पहुंचने पर नायक व घोड़े शेरा का ग्रामीणों ने गाजे–बाजे के साथ स्वागत किया। रूबी की यह उपलब्धि केवल एक प्रतियोगिता में मिली सफलता नहीं, बल्कि अपने जुनून को पहचान देने के संघर्ष की कहानी भी है। किन्नर समाज से जुड़ी रूबी सामाजिक कार्यों में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेती हैं। जरूरतमंदों की मदद के साथ ही घुड़सवारी और घोड़ों के प्रति अपने लगाव को उन्होंने खेल के मैदान तक पहुंचाया है।

महाराष्ट्र के परभणी में एआर स्टड फार्म की ओर से आयोजित देशस्तरीय शाही रेवाल घुड़चाल स्पर्धा में देश के विभिन्न राज्यों से आए घोड़ों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में शेरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शेरा के सवार दिलखुश थे। दूसरे स्थान पर रहने पर शेरा को एक लाख 31 हजार रुपये नकदी और 300 ग्राम चांदी का पदक प्रदान किया गया। हालांकि, रूबी नायक प्रतियोगिता के परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं।

उनका दावा है कि शेरा ने वास्तव में प्रथम स्थान हासिल किया था, लेकिन आयोजन समिति की ओर से की गई गड़बड़ी के कारण उसे दूसरे स्थान पर घोषित कर दिया गया। उन्होंने इस निर्णय पर नाराजगी जताते हुए प्रतियोगिता के परिणाम पर सवाल उठाए। नायक शेरा के साथ गांव पहुंचीं तो उत्सव जैसा माहौल बन गया। रामाशीष सिंह के दरवाजे पर ग्रामीणों ने ढोल–नगाड़ों और गाजे–बाजे के साथ उनका स्वागत किया। फूल–मालाएं पहनाकर रूबी व शेरा का अभिनंदन किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि रूबी ने सामाजिक सेवा के साथ खेल के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी उपलब्धि से रहसू जनूबी पट्टी गांव ही नहीं, पूरे कुशीनगर जिले का गौरव बढ़ा है। रामाशीष सिंह, राजेंद्र जायसवाल, पायल किन्नर, खुशबू, काजल, जूही, मधु, प्रियंका, समतोला, रोशनी, पलक, जारीना गुरु, सरोज, रसभरी और सोनी आदि मौजूद रहे।

# संविधान दिवस पर सभी विद्यालयों में सुबह होगा प्रस्तावना का सामूहिक पाठ

**संवाददाता–बलरामपुर।** संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को जिले के सभी विद्यालयों में एक स्वर, एक संविधान कार्यक्रम आयोजित करने की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। सुबह ठीक नौ बजे एक साथ छात्र–छात्राएं, शिक्षक व विद्यालय परिवार भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) और मूल कर्तव्यों का सामूहिक पाठ करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा–निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से सामूहिक पाठ का विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने की अनूठी पहल की गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में संविधान के प्रति सम्मान, लोकतांत्रिक चेतना और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव यशपाल वर्मा ने बताया कि एक स्वर, एक संविधान कार्यक्रम के सफल व सुव्यवस्थित आयोजन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) मृदुला आनंद के साथ बैठक कर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। बैठक में विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को कार्यक्रम की रूपरेखा और आयोजन से जुड़े आवश्यक दिशा–निर्देशों की जानकारी दी गई है। सभी विद्यालयों को निर्धारित समय पर सामूहिक पाठ कराने व उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए विद्यार्थियों को 50–50 के समूहों (ब्लॉक) में खड़ा किया जाएगा। प्रत्येक समूह के साथ एक शिक्षक की तैनाती अनिवार्य होगी, जिससे सामूहिक पाठ के दौरान अनुशासन व व्यवस्था बनी रहे। संविधान की उद्देशिका के बाद मूल कर्तव्यों का सामूहिक पाठ ठीक सुबह नौ बजे शुरू कराया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में कार्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान दो स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित करनी होगी। कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग सुबह 8:55 से 9:05 बजे तक कराई जाएगी। रिकॉर्डिंग में तारीख व समय स्पष्ट रूप से दिखाई देना अनिवार्य है, जिससे आयोजन के निर्धारित समय पर संपन्न होने का प्रमाण उपलब्ध रहे। सभी विद्यालयों को वीडियो रिकॉर्डिंग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दफ्तर में भेजनी होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव यशपाल वर्मा ने प्रधानाचार्यों व प्रबंधकों से निर्देशों का पालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। एक स्वर, एक संविधान कार्यक्रम में सामूहिक पाठ के साथ ही सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संवैधानिक समझ विकसित करने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (एमसीक्यू क्विज), प्रश्नोत्तरी संकलन व कला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा के सदस्यों के योगदान, मौलिक अधिकारों और मूल कर्तव्यों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता और अखंडता जैसे संवैधानिक आदर्शों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक महत्व को याद करने के उद्देश्य से हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था, जबकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाला यह सामूहिक कार्यक्रम विद्यार्थियों को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान में निहित मूल्यों से जोड़ने का माध्यम बनेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव यशपाल वर्मा ने कहा कि 'एक स्वर, एक संविधान' कार्यक्रम केवल सामूहिक पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से नई पीढ़ी को संविधान के प्रति जागरूक और अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति सजग बनाना है। उन्होंने सभी विद्यालयों से निर्धारित समय, व्यवस्था व रिकॉर्डिंग संबंधी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है

# मतदाता सूची में अपात्रों के नाम जोड़ने पर होगी कार्रवाई –डीएम

**संवाददाता–गोण्डा।** मतदाता सूची में संख्या बढ़ाने के लिए किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम न जोड़ा जाए। वहीं, किसी पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल होने से छूटना नहीं चाहिए। इसमें लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश बुधवार दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम रमेश रंजन ने दिए। डीएम की अध्यक्षता में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। डीएम ने कहा– जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची त्रुटिरहित तैयार करना प्रशासन की प्राथमिकता है। जिन वास्तविक मतदाताओं के नाम किसी कारण से कट गए हैं या जो युवा पहली बार मतदाता बने हैं, उनके नाम सूची में जरूर शामिल किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी तहसील या विधानसभा क्षेत्र से गलत नाम जोड़े जाने की शिकायत मिलती है तो जांच कराई जाएगी। आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।

बुधवार दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम रमेश रंजन ने अधिकारियों को दिए निर्देश।

डीएम ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के माध्यम से अधिक से अधिक नए मतदाताओं के फॉर्म–6 भरवाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय–सीमा में मिलने वाले सभी दावों और आपत्तियों का पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बूथों पर लगने वाले कैंपों के बारे में भी लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र मतदाता अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकें।

बैठक में मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि बीएलए के माध्यम से छूटे हुए और नए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही गलत नाम शामिल होने से रोकने में भी सहयोग किया जाएगा।

# चीनी मिल में ब्वायलर का विधि–विधान से हुआ पूजन

**संवाददाता–महराजगंज।** जेएचवी चीनी मिल गड़ौरा में बुधवार को विधि–विधान के साथ ब्वायलर पूजन कराया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ब्वायलर में अग्नि प्रवेश कराया गया और हवन के साथ आगामी पेराई सत्र के सफल संचालन की कामना की गई। पूजन के साथ ही मिल में गन्ना पेराई शुरू करने की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। शासन के आदेश पर पेराई सत्र शुरू करा दिया जाएगा।

ब्वायलर पूजन पं. अमरनाथ उर्फ रामू दूबे ने संपन्न कराया। मुख्य यजमान के रूप में महाप्रबंधक इंजीनियरिंग विजय कुमार दीक्षित ने पूजन–अर्चन किया। उनके साथ महाप्रबंधक गन्ना विश्वामित्र सिंह भी पूजन में शामिल रहे। पूजन के दौरान नारियल फोड़कर परंपरा निभाई गई और हवन के बाद ब्वायलर में अग्नि प्रज्वलित की गई। महाप्रबंधक इंजीनियरिंग विजय कुमार दीक्षित ने बताया कि गुरुवार व शुक्रवार को मास्टर ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद मिल पेराई के लिए तैयार रहेगी। शासन से संचालन का आदेश मिलते ही चीनी मिल में पेराई शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मिल की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और तकनीकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा चुका है। ब्वायलर पूजन में मिल के इंजीनियर सीडी मिश्र, संतोष सिंह, वृजवासी सिंह, विजय विक्रम सिंह, जयनारायण यादव, स्टोर इंचार्ज विश्वजीत मिश्र, केमिस्ट अशोक, प्रखर, इंस्ट्रूमेंट विभाग से पंकज, शिवेश यादव, आनंद, शारदानंद यादव, अमला यादव, शिशुपाल, छोटई, सत्यनारायण, सुरेश, नीलेश राव, संजय मिश्र, यशवंत, सीडीओ आलोक कुमार, असिस्टेंट कैन मैनेजर अजय कुमार, कृष्णमोहन तिवारी, रामायण शर्मा व मानवेन्द्र सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही लक्खीचंद वर्मा, जयराम यादव, रोशन अली, गिरिजेशगुप्ता, परशुराम और हरि सिंह सहित कई किसान भी पूजन में शामिल हुए।

# ढहाई गई मजार पर दिव्या मित्तल और शलभ मणि आमने–सामने



**संवाददाता–देवरिया।** गोरखपुर रोड स्थित ढहाई गई मजार को लेकर पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व डीएम दिव्या मित्तल ने एक पॉडकास्ट में आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल के दौरान मजार पर बुलडोजर चलाने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने दावा किया कि मजार कमेटी ने अतिक्रमण हटा लिया था, इसके बावजूद मजार गिराने का दबाव बनाया जा रहा था। अब उनके बयान पर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कुछ अधिकारी हवा का रुख देखकर अपने तेवर बदल लेते हैं। दिव्या मित्तल के अनुसार, देवरिया में जिलाधिकारी रहते हुए उनसे कहा जाता था कि दूसरे जिलों में मस्जिदों और मजारों पर बुलडोजर चल रहा है तो यहां कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने इसे एक जनप्रतिनिधि के वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा मामला बताया। उनका दावा है कि मजार कमेटी की ओर से अतिक्रमण पहले ही हटा लिया गया था, इसके बावजूद उन पर मजार गिराने का दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में मजार को गिरने नहीं दिया, लेकिन इसके बाद उनका तबादला हो गया। दिव्या मित्तल ने यह भी दावा किया कि मजार आज भी मौजूद है और वहां रोजाना चादर चढ़ाई जाती है।

दिव्या मित्तल के आरोपों पर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि उन्हें अधिकारियों के बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन बहुत से अधिकारी ऐसे होते हैं जो हवा का रुख देखकर अपने तेवर बदल लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब नौकरी बचाने की जरूरत थी तो मजार ढहा दी गई और अब राजनीति की जरूरत है तो मजार के नाम पर आंसू बहाए जा रहे हैं।

विधायक ने कहा कि उनके मुताबिक संबंधित मजार अवैध थी और उसे गिराया जाना था। इसी वजह से कार्रवाई कराई गई। उन्होंने कहा कि किसी के दबाव में अच्छा काम हुआ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि, एक समय मजार गिराने और दूसरे समय उसके नाम पर भावुकता जताने के रुख पर उन्होंने सवाल उठाया।

# 225 कुपोषित बच्चों को पोषण किट मिली



**संवाददाता–श्रावस्ती।** 'परंपरा से पोषण' अभियान के तहत 225 अतिकुपोषित बच्चों और उनकी माताओं को पोषण सामग्री दी गई। बुधवार शाम 4:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में हुए कार्यक्रम में लोहे की कड़ाही, पोषण किट और पौष्टिक खाद्य सामग्री बांटी गई। मंडलायुक्त देवी शक्ति नागपाल की पहल पर यह अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में विधायक रामफेरन पांडेय, जिलाध्यक्ष डॉ. मिश्रीलाल वर्मा, जिलाधिकारी मनोज कुमार राय, मुख्य विकास अधिकारी शिशिर कुमार सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि सुनील तिवारी मौजूद रहे। लाभार्थियों को गुड़, भुना चना, सत्तू, फोर्टिफाइड टेक होम राशन, कैल्शियम और ओआरएस–जिंक दिया गया। अधिकारियों ने उन्हें संतुलित आहार के बारे में भी बताया।

अभियान में दी गई लोहे की कड़ाही का उद्देश्य भोजन में आयरन की मात्रा बढ़ाना और महिलाओं व बच्चों में खून की कमी से बचाव को बढ़ावा देना है। स्थानीय स्तर पर मिलने वाले पौष्टिक खाद्य पदार्थों को रोज के भोजन में शामिल करने पर भी जोर दिया गया।

जिलाधिकारी मनोज कुमार राय ने कहा कि अभियान के जरिए क्षेत्रीय खानपान की परंपराओं को फिर से अपनाने और माताओं–बच्चों को पोषण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। कुपोषण से निपटने के लिए आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग बच्चों की नियमित निगरानी, स्वास्थ्य जांच और पोषण संबंधी सलाह देंगे। विधायक ने मातृ और शिशु पोषण के लिए पौष्टिक भोजन अपनाने की अपील की। मुख्य विकास अधिकारी ने विभागों के बीच तालमेल और लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

# अपनी मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल पर वीबी–जी रामजी के कर्मचारी

**संवाददाता–महराजगंज।** मानदेय वृद्धि समेत लंबित मांगों को लेकर वीबी–जी रामजी योजना के तहत कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों व अन्य संविदा कर्मियों की कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पांचवें दिन भी जारी रही। बुधवार को सदर ब्लॉक परिसर में जिलाध्यक्ष ब्रह्मानंद के नेतृत्व में कर्मचारियों ने धरना दिया। इसमें ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर व अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी शामिल रहे। कर्मचारियों ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी।



जिलाध्यक्ष ब्रह्मानंद ने कहा कि प्रदेश के अन्य विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की गई है, लेकिन वीबी–जी रामजी योजना के कार्मिकों के मानदेय में अब तक बढ़ोतरी नहीं हुई है। लखनऊ के डिफेंस पार्क में मुख्यमंत्री की ओर से एचआर पॉलिसी लागू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक इसका शासनादेश जारी नहीं हुआ। इसी तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा के बाद भी शासनादेश जारी नहीं किया गया है। कर्मचारियों ने कहा कि घोषणाओं के बावजूद मांगों पर निर्णय नहीं होने से उनमें असंतोष है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका जवाब देंगे। इस दौरान दिनेश शर्मा, ओमप्रकाश आर्य, अयोध्या वर्मा, रीता गुप्ता, जितेंद्र चौहान, परमजीत, प्रमोद राय, असगर अली, अंजली, ऊषा कन्नौजिया, चिन्नू प्रसाद, ओमप्रकाश, अम्बिका प्रसाद, चन्द्रिका, सर्वेश आदि मौजूद रहे। हड़ताल के क्रम में ग्राम रोजगार सेवक व अन्य कार्मिक 27 नवंबर को ब्लॉक से जिला मुख्यालय पर पैदल मार्च निकालेंगे। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर दोपहर 12:30 बजे सदर ब्लॉक से मार्च शुरू होगा, जो कलक्ट्रेट पहुंचकर समाप्त होगा। कर्मचारी मुख्यमंत्री को संबोधित मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेंगे। इस संबंध में ग्राम रोजगार सेवक संघ की ओर से एसडीएम सदर को प्रार्थना पत्र देकर पैदल मार्च निकालने की अनुमति मांगी गई है।

# सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर जोर, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने को कहा




**संवाददाता–बलरामपुर।** भाजपा ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार दोपहर तीन बजे तुलसीपार्क स्थित जिला कार्यालय अटल भवन में बैठक हुई। इसमें संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और चुनावी तैयारियों

बैठक में मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के सह–प्रभारी और झारखंड से राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पार्टी का संगठन और समर्पित कार्यकर्ता उसकी पूंजी हैं। उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की अपील की।

वर्मा ने कहा कि जनता से लगातार संपर्क करना, सरकार की योजनाओं की जानकारी देना और पार्टी की विचारधारा लोगों तक पहुंचाना संगठन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं को आपसी तालमेल और जिम्मेदारी के साथ संगठन की गतिविधियां आगे बढ़ानी चाहिए।

क्षेत्रीय मंत्री गौरव भाटिया ने कहा कि चुनाव के लिए अभी से संगठन की सक्रियता बढ़ाने और बूथ स्तर पर तैयारी करने की जरूरत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सुझावों से जुड़ने को कहा। उन्होंने कहा कि संगठन की एकजुटता, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनसंवाद चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। बैठक में जिला प्रभारी राज किशोर मौर्य, जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष चन्द्र प्रकाश सिंह श्गुड्डूश, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राकेश सिंह और पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह मौजूद रहे।

पूर्व सांसद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रावस्ती दद्दन मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर आरती तिवारी, सदर विधायक पल्टू राम, तुलसीपुर विधायक कैलाशनाथ शुक्ला, उतरौला विधायक राम प्रताप वर्मा, पूर्व विधायक गैसड़ी शैलेश सिंह 'शैलू' और बिंदु विश्वकर्मा भी बैठक में शामिल हुए। पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

# चार मंदिरों में चोरी का आरोपी गिरफ्तार




**संवाददाता–देवरिया।** मंदिरों में चोरी करने के आरोपी को भलुअनी पुलिस ने बुधवार दोपहर दो बजे गिरफ्तार किया। उसकी पहचान बरहज थाना क्षेत्र के गौरा बरहज तिवारीपुर गांव के अशफाक (26), पुत्र स्व. नूर आलम के रूप में हुई है। 13 अक्टूबर को भलुअनी थाना क्षेत्र के बढ़या फुलवरिया गांव स्थित शिव मंदिर में चोरी हुई थी। अमित तिवारी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच के दौरान अशफाक का नाम सामने आया। बुधवार को मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने उसे सोनाड़ी मोड़ से बरौली जाने वाले रास्ते के पास गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में अशफाक ने भलुअनी के शिव मंदिर के अलावा बनकटा थाना क्षेत्र के सोहनपुर रामजानकी मंदिर और रामपुर बुजुर्ग हनुमान मंदिर में चोरी करना स्वीकार किया। उसने लार थाना क्षेत्र के देवामठ शिव मंदिर में भी चोरी की बात कबूली। पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल (न्च52 9660) भी बरामद की है।

पुलिस ने अशफाक के पास से दो पीतल के कलश, तांबे का सर्प, पांच पीतल के घंटे, छह छोटी घंटियां, पांच लोटे, पीतल का जग, पीतल और स्टील की दो बाल्टियां, पांच दीपक, अभिषेक पात्र, लोहे का त्रिशूल, पीतल के गिलास, चौमुखा स्टैंड और अगरबत्ती स्टैंड बरामद किए हैं।

इसके अलावा बैग से हथौड़ी, छेनी, वायर कटर और रिंच समेत अन्य औजार भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक, अशफाक के खिलाफ भलुअनी, लार, सलेमपुर और बनकटा थानों में चोरी और चोरी का सामान मिलने से जुड़े कई केस दर्ज हैं। उसे गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

# बीमार पिता की टूटती सांसों को देख छटपटाता रहा बेटा, आधे घंटे तक लगे ट्रैफिक जाम के चलते मौत

**संवाददाता–देवरिया।** पिता की बिगड़ती सांसें व उन्हें बचाने की उम्मीद में छटपटाता बेटा। सामने वाहनों की लंबी कतार व निकलने का कोई रास्ता नहीं। वह कभी लोगों से रास्ता देने की गुहार लगाता तो कभी वाहन आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन जाम में आधे घंटे तक फंसा रहा। जब किसी तरह अस्पताल पहुंचा तो पिता की सांसें थम चुकी थीं। चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने नगर में जाम और सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण की समस्या फिर उजागर कर दी है।



मईल थाना क्षेत्र के कपूरी गांव निवासी 80 वर्षीय कलाधर मणि त्रिपाठी की बुधवार सुबह तबीयत बिगड़ गई। हालत गंभीर देख बेटा शंभू मणि त्रिपाठी उन्हें निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर लेकर निकल पड़ा। गांधी चौक से आगे स्टेशन रोड पर सड़क की दोनों पटरियों पर सब्जी की दुकानें लगी होने के कारण वाहनों की लंबी कतार लगी थी। इससे रास्ता पूरी तरह जाम हो गया था।

पिता की बिगड़ती हालत देख शंभू मणि त्रिपाठी वाहन का शीशा उतारकर सड़क खाली कराने के लिए चिल्लाते रहे। वह लोगों से रास्ता देने की गुहार लगाते रहे, लेकिन जाम के चलते वाहन आगे नहीं बढ़ सके। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह उनकी कार जाम से बाहर निकली और अस्पताल पहुंची। वहां चिकित्सक ने जांच के बाद कलाधर मणि त्रिपाठी को मृत घोषित कर दिया।

सीओ गौरव सिंह ने कहा कि स्टेशन रोड पर लगने वाले जाम से निजात के लिए कई बार सब्जी दुकानदारों के साथ बैठक की गई है। बड़े वाहनों को खड़ा करने के लिए समय निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद जाम लग रहा है तो दुकानदारों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी।

## डंपर की टक्कर से पिता–पुत्र की मौत



**संवाददाता–गोरखपुर।** पीपीगंज थाना क्षेत्र के तुर्कवलिया चौराहे पर मंगलवार की देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार पिता–पुत्र की मौत हो गई। दोनों शादी समारोह से घर लौट रहे थे। अज्ञात वाहन की टक्कर से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंगल कौड़िया ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। बढ़या गांव निवासी मनीराम गुप्ता (52) मिठाई का छोटा कारोबार करते थे। उनका बेटा अमन गुप्ता उर्फ मोनू (25) सहज जनसेवा केंद्र चलाता था। मंगलवार रात करीब 12 बजे दोनों बाइक से शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। तुर्कवलिया गांव के मोड़ पर पहुंचते ही किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। ग्रामीणों के अनुसार, हादसे में खनन कार्य में लगा डंपर शामिल था। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पीपीगंज पुलिस दोनों को अस्पताल ले गई लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से दुर्घटना करने वाले वाहन का पता लगाया जा रहा है।

मनीराम के परिवार में पत्नी, एक बेटा और 20 वर्षीय बेटी हैं। अमन बड़ा बेटा था। दोनों भाई–बहन की अभी शादी नहीं हुई थी।

## कमरे में पंखे से लटका मिला युवक का शव

**संवाददाता–अयोध्या।** बुधवार को 22 वर्षीय युवक का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। घरवालों ने देखा तो बिलख उठे। वह शाम को निमंत्रण से आकर सोने गया था। सुबह उसकी लाश मिली। खबर फैली तो ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली।

घटना तारुन थाना क्षेत्र के केशरुआ बुजुर्ग कोटवा गांव की है। गांव निवासी आलोक (22) का शव फंदे से लटकता मिला। बताया गया कि आलोक मंगलवार को एक निमंत्रण में शामिल होने गया था। देर रात घर लौटने के बाद वह छत पर बने कमरे में सोने चला गया। सुबह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आया तो परिजनों ने जाकर देखा। कमरे के बाहर से आवाज देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उन्होंने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे परिजनों ने आलोक का शव पंखे के हुक से रस्सी के सहारे लटका देखा। थाना प्रभारी लालचंद सरोज ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

## अयोध्या में 29 नवंबर को रामलला का तिलक समारोह, नेपाल के जनकपुर से आएंगे 51 तिलकहरू

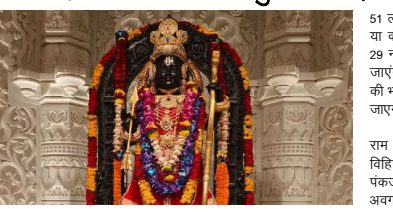

**संवाददाता–अयोध्या।** भारत–नेपाल के सदियों पुराने पारंपरिक संबंध को तिलकोत्सव के माध्यम से फिर प्रगाढ़ करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। माता जानकी के मायके जनकपुर के लोग अपने पाहुन (दामाद) भगवान श्रीराम का तिलक चढ़ाने के लिए इसी माह 29 नवंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामलला के तिलकोत्सव में इस बार 51 तिलकहरू मध्येश प्रदेश के समामुख (विधानसभा अध्यक्ष) रामाशीष यादव के नेतृत्व में यहां पहुंचेंगे। तिलकहरुओं में जनकपुर के मेयर मनोज साह, जानकी मंदिर के महांत राम तपेश्वर दास वैष्णव, नेपाल विहिप के केंद्रीय सदस्य मनोहर साह, विहिप के ६ नुषा जिलाध्यक्ष संतोष साह सहित अन्य शामिल रहेंगे। इनमें दस महिलाएं भी होंगी, जो सीता जी की सखियां बनकर आएंगी। अयोध्या के रामसेवकपुरम में सादे समारोह में भगवान राम का तिलक चढ़ेगा।

तिलकहरुओं की ओर से बरात लाने की सहमति व्यक्त करके भार (नेग) स्वरूप सोना–चांदी के आभूषण, फल, मेवा व अन्य उपहार भेंट किया जाएगा। तिलक चढ़ने के बाद प्रतीकात्मक रूप से अयोध्या से जनकपुर के लिए राम बरात प्रस्थान करेगी। बरात में स्थानीय साधु–संतों के अलावा विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। विहिप के धनुषा जिलाध्यक्ष संतोष साह ने बताया कि जनकपुरधाम में गत दिनों हुई बैठक में तिलकोत्सव की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस दौरान यह तय किया गया है कि जनकपुर से 51 लोग तिलकहरू के रूप में अयोध्या के लिए 28 नवंबर को चलेंगे। 29 नवंबर की सुबह अयोध्या पहुंच जाएंगे। रामसेवकपुरम में गत वर्ष की भांति रामलला का तिलक चढ़ाया जाएगा।

अयोध्या से प्रस्थान करने वाली राम बरात समिति के संयोजक व विहिप के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज को तिथि निर्धारित करके अवगत करा दिया गया है। तैयारी बैठक में जनकपुर के मेयर मनोज साह व जानकी मंदिर के छोटे महांत राम रोशन दास सहित अन्य पदाधिकारियों ने तिलकोत्सव की नई परंपरा शुरू की थी, जिसके अंतर्गत 18 नवंबर 2024 को रामसेवकपुरम में रामलला का तिलक चढ़ाया गया था। इस समारोह में मध्येश प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह अपने पांच कैबिनेट मंत्रियों व जनकपुर मेयर सहित 501 लोगों के साथ अयोध्या पहुंचे थे। यहां राजा दशरथ के रूप में विहिप के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपतराय ने सारी रस्में निभाई थीं।

## अकबरपुर में ओमप्रकाश राजभर की एंट्री से बदलेगा सियासी समीकरण



**संवाददाता–अम्बेडकरनगर।** अंबेडकरनगर में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अकबरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।

अकबरपुर विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास इस संभावित मुकाबले को खास बनाता है। यहां रामअचल राजभर का लंबे समय से प्रभाव रहा है। 1993 से 2022 के बीच हुए सात विधानसभा चुनावों में उन्होंने छह बार जीत दर्ज की है। 2012 में समाजवादी पार्टी के राममूर्ति वर्मा ने उन्हें हराया था। इसके बाद 2017 में बसपा और 2022 में सपा के टिकट पर रामअचल राजभर ने फिर जीत हासिल की। ओमप्रकाश राजभर के अकबरपुर से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद जातीय और राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दोनों नेताओं की पहचान राजभर समाज की राजनीति से जुड़ी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि राजभर समाज के मतदाताओं के बीच दोनों नेताओं की पकड़ किस तरह सामने आती है।

दूसरी ओर, अकबरपुर में सपा का मजबूत आधार और रामअचल राजभर का पुराना चुनावी प्रभाव भी संभावित मुकाबले को महत्वपूर्ण बनाता है। भाजपा और छव। की रणनीति, सुभासपा की भूमिका और विपक्षी दलों की चुनावी तैयारी भी इस सीट के समीकरणों को प्रभावित कर सकती है।

हालांकि 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है। गठबंधन, प्रत्याशियों और सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम तस्वीर साफ होना बाकी है। लेकिन ओमप्रकाश राजभर के इस ऐलान ने अकबरपुर को जिले की चर्चित राजनीतिक सीटों में शामिल कर दिया है।

# सपा रोड शो हादसाः पुलिस ने कोर्ट को सौंपी सीसीटीवी फुटेज, रिमांड मंजूर

**संवाददाता–गोरखपुर।** सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान भाजपा नेता ओंकार सिंह के 14 वर्षीय बेटे आर्यवर्धन की मौत के मामले में पुलिस ने मंगलवार को सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में प्रस्तुत किया। विवेचक ने फुटेज के साथ प्रमाण पत्र भी दाखिल किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने फुटेज का अवलोकन करने के बाद तीनों आरोपितों मनोज यादव, मृत्युंजय यादव उर्फ विट्ठू और योगेश यादव की रिमांड 25 नवंबर तक मंजूर कर ली। हालांकि, कोर्ट ने फुटेज में घटना के संबंध में अभियोजन के कथानक से कुछ अलग स्थिति दिखाई देने पर विवेचक से सवाल भी किए हैं। उसे 25 नवंबर तक यह स्पष्ट करने का अवसर दिया गया है कि उपलब्ध वीडियो और केस डायरी में दर्ज साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों की अग्रिम रिमांड किन आधारों पर दी जाए।

दरअसल, 21 नवंबर को तीनों आरोपितों की पहली रिमांड मंजूर करते हुए अदालत ने विवेचक को सीसीटीवी फुटेज संरक्षित कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। मंगलवार को तीनों आरोपित वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस की ओर से संकलित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से आरोपितों की संलिप्तता साबित नहीं होती। वहीं अभियोजन पक्ष ने विवेचना जारी होने और आगे की जांच के लिए रिमांड की जरूरत बताते हुए 14 दिन की अग्रिम रिमांड मांगी।

विवेचक की ओर से प्रस्तुत सीसीटीवी फुटेज में घटना से कुछ क्षण पहले देवरिया मार्ग पर महादेव झारखंडी गेट के सामने एक सरकारी बस खड़ी होती दिखाई दे रही है। इसके कुछ देर बाद पीले रंग की जेसीबी बस के बगल से गुजरती दिखती है। फुटेज के अवलोकन में जेसीबी की गति कुछ असामान्य नजर आई, लेकिन ड्राइवर होने के कारण मृतक और उसका स्कूटर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जेसीबी के गुजरने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटती दिख रही है। अभियोजन की ओर से भी फुटेज देखने के बाद यही बताया गया कि बस के पीछे जेसीबी उछलती हुई आगे निकलती दिखाई दे रही है। अदालत के अवलोकन में सामने आया कि फुटेज में जेसीबी के सामने कोई व्यक्ति या वाहन आता दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही घटना स्थल से निकलने के बाद जेसीबी को दोबारा आगे–पीछे होते हुए भी नहीं देखा गया, जबकि अभियोजन का आरोप है कि चालक ने जानबूझकर जेसीबी को आगे–पीछे कर कई बार टक्कर मारी थी। कोर्ट ने इसे अभियोजन के कथानक से अलग स्थिति माना। इसके बाद तीनों आरोपितों की रिमांड 25 नवंबर तक मंजूर करते हुए विवेचक को उपलब्ध वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर रिमांड के औचित्य पर जवाब देने का निर्देश दिया।

## दो सड़क हादसे, छह घायल पांच की हालत गंभीर

**संवाददाता–सिद्धार्थनगर।** भारत भारी मेले के दौरान बुधवार दोपहर दो अलग–अलग सड़क हादसों में छह लोग घायल हो गए। पांच घायलों की हालत गंभीर थी। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेंवा सीएचसी से जिला अस्पताल बस्ती रेफर किया गया। दोनों हादसों के बाद वाहन चाल पहला हादसा बुधवार दोपहर करीब एक बजे बेंवा–भारत भारी मार्ग पर पटखौली स्थित देसी शराब ठेके के पास हुआ। बस्ती जिले के छपिया खास निवासी विवेक (19), रामसागर (18) और राज (11) बाइक से मेला देखकर लौट रहे थे। तभी भारत भारी की ओर से आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

हादसे में तीनों घायल हो गए। विवेक और रामसागर की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल बस्ती रेफर किया गया। राज का इलाज जारी है। दूसरा हादसा रुद्धौली–डुमरियागंज मार्ग पर परसा हुसैन के पास हुआ। रिश्तेदार से मिलकर मेले में जा रहे गिरधर निवासी रवि (19), रूबी (17) और अंदेवरा निवासी मंगीता (16) की बाइक को एक अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल बस्ती रेफर किया गया।

## 29 घंटे बाद नदी में मिला किशोर का शव

**संवाददाता–अम्बेडकरनगर।** स्थानीय थाना क्षेत्र के बिड़हर पुल से सरयू नदी में छलांग लगाने वाले 17 वर्षीय किशोर प्रभात गिरि का शव करीब 29 घंटे की तलाश के बाद नदी से बरामद कर लिया गया। किशोर का शव मिलने की खबर से परिवार में चीख–पुकार मच गई। मंगलवार से बेटे की सलामती की उम्मीद लगाए बैठे परिजनों पर बुधवार को दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मौके पर पहुंचे परिजन शव देखकर फूट–फूटकर रोने लगे। कटका थाना क्षेत्र के पिड़ोरिया निवासी प्रदीप कुमार गिरि का पुत्र प्रभात मंगलवार सुबह करीब पांच बजे घर से कोचिंग जाने की बात कह कर निकला था। बताया जाता है कि सोमवार रात घर में किसी बात को लेकर नाराजगी के बाद वह घर से निकला था। मंगलवार सुबह बिड़हर पुल पहुंचकर उसने सरयू नदी में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही जहांगीरगंज थानाध्यक्ष रितेश पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और नदी में तलाश शुरू कराई। हालांकि सफलता नहीं मिल सकी। इस बीच बुधवार को सुबह पुलिस प्रशासन के साथ प्रतापगढ़ से आई एनडीआरएफ की टीम ने नदी में खोज अभियान चलाया। मंगलवार से लगातार चल रही तलाश के बाद बुधवार को पुल के नीचे नदी से प्रभात का शव बरामद कर लिया गया। शव मिलने के बाद पुलिस प्रशासन पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुट गया। नायब तहसीलदार कौशल किशोर, आलापुर कानूनगो मुन्नी लाल, लेखपाल भूपेंद्र कुमार और रुद्र मणि शुक्ला समेत पुलिस टीम मौजूद रही। प्रभात की घटना के बाद बिड़हर पुल पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल के दोनों ओर मजबूत बैरिकेडिंग लगाए जाने की मांग पहले भी समाजसेवियों और क्षेत्रीय लोगों की ओर से उठाई जाती रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। लोगों के मुताबिक, पुल पर पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में पुल के दोनों किनारों पर सुरक्षा बैरिकेडिंग और अन्य जरूरी इंतजाम किए जाने की जरूरत है, जिससे ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिल सके।

## आम के बगीचे में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

**संवाददाता–गोरखपुर।** गुलरिहा क्षेत्र के करमहां बुजुर्ग गांव के बरई टोला में बुधवार सुबह एक युवक का शव आम के बगीचे में पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। युवक की पहचान नहीं हो सकी है। गुलरहिया पुलिस आसपास के गांवों में भी सूचना देकर शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। शरीर पर चोट के निशान मिलने अशंका है की हत्या कर शव को फंदे से लटकाया गया होगा। गांव के पूर्व प्रधान के आम के बगीचे की ओर बुधवार सुबह कुछ ग्रामीण गए थे। इसी दौरान उनकी नजर पेड़ से लटक रहे युवक के शव पर पड़ी। यह खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। काफी प्रयास के बाद भी युवक की पहचान नहीं हो सकी।

ग्रामीणों के मुताबिक, युवक के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। वहीं, चादर के फटे टुकड़े से शव को पेड़ पर लटकाए जाने की बात सामने आई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए ग्रामीणों ने युवक की पिटाई कर हत्या किए जाने के बाद शव लटकाने की आशंका जताई है। सूचना पर भटहट चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा की कार्रवाई शुरू की। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि अभी मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। युवक की पहचान कराने के साथ ही मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

## मांगों को लेकर रोजगार सेवकों ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन

**संवाददाता–अम्बेडकरनगर।** ग्राम रोजगार सेवक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जलालपुर ब्लॉक पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 17 नवंबर से प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा घोषित अनिश्चितकालीन धरने में शामिल होने और मांगें पूरी होने तक कार्य बहिष्कार करने की जानकारी दी गई। रोजगार सेवकों ने कैशलेस इलाज, बकाया मानदेय का भुगतान, ऐप के माध्यम से मानदेय में कटौती बंद करने, मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह करने और ऑनलाइन उपस्थिति की समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। धरने को प्रधान संघ के अध्यक्ष ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने मजदूरों की मजदूरी के भुगतान में देरी का मुद्दा भी उठाया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष विजेंद्र कुमार, अमित कुमार, परशुराम, पूजा पटेल, रंभा देवी, कुशलावती, राजकुमार और विकास चौधरी समेत कई रोजगार सेवक मौजूद रहे।

### अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

अदालत–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला–बस्ती

मूलवाद सं0–369/2025

ज्वाला प्रसाद

बनाम

रामानुज मिश्रा आदि

1–रामानुज मिश्रा पुत्र राजबली 2. श्रीमती शिथिला मिश्रा पत्नी रामानुज मिश्रा साकिन बैजीपुर तप्पा मथौली परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती वर्तमान पता पूर्व शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 निकट सदर ब्लाक कार्यालय ब्लाक रोड गांधी नगर बस्ती

**तारीख पेशी 17–12–2026**

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 17 माह 12 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 25 माह 11 सन 2026 ई0 जारी किया गया। –द0 हाकिम

### अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

अदालत–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) एफ0टी0सी0 महोदय सिद्धार्थनगर जिला– सिद्धार्थनगर

इस्लामिया रहमानिया एजुकेशनल सोसाइटी

बनाम

गौरव आदि

2. सद्रुन्निशा उम्र करीब 71 वर्ष पत्नी मोहम्मद हारून जन्मतः निवासी ग्राम–डुमरियागंज, तप्पा–हल्दीर, परगना– रसूलपुर, तहसील–डुमरियागंज, जिला–सिद्धार्थनगर, हाल मकाम–बेलवाडाड़ी, पोस्ट–गांधीनगर, तहसील–बस्ती, जिला–बस्ती

–प्रतिवादी द्वितीय पक्ष

**तारीख पेशी 12–01–2027**

प्रतिवादी ने आपके विरुद्ध के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक **12–01–2027** को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिवक्ता प्लीडर द्वारा उप संजात हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संजात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिये जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर ऊपर बतायी गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश

### अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

अदालत–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती

मूलवाद सं0–792/2025

मुनेसर आदि

बनाम

मनोज कुमार आदि

1–मनोज कुमार उम्र लगभग 45 वर्ष 2– आशाराम उम्र लगभग 50 वर्ष 3– निलेश कुमार उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्रगण रामदेव 4– लल्लू प्रसाद उम्र लगभग 52 वर्ष 5–राम प्रताप उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्रगण राम कुमार 6–जगदीश कुमार उम्र लगभग 48 वर्ष 7–प्रकाश उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्रगण सुखदेव निवासीगण ग्राम– तेनुआ असनहरा तप्पा –आदमपुर परगना –रसूलपुर तहतील–मानपुर, पोस्ट– करमहिया जिला बस्ती

–प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग

8. बुधई उम्र लगभग 56 वर्ष पुत्र भिखारी ग्राम– तेनुआ असनहरा तप्पा –आदमपुर परगना –रसूलपुर तहतील–मानपुर, पोस्ट– करमहिया जिला बस्ती

–प्रतिवादी द्वितीय वर्ग

**तारीख पेशी 29–01–2027**

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 29 माह 01 सन 2027 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

### अदालती नोटिस

सन् 1890 के अधिनियम 8 की धारा 11 के अधीन सूचना

न्यायालय– श्रीमान सत्र न्यायधीश महोदय जनपद सिद्धार्थनगर

प्रकीर्णवाद सं0 74/2026

अजीजूनिशा उर्फ जूबैदा खातून

बनाम

उ0प्र0 राज्य /जिलाधिकारी

1–उ0प्र0 राज्य /जिलाधिकारी

विपक्षी प्रथम पक्ष

2–साहिद हुसैन उर्फ गुंगा बहरा उर्फ आरिफ हुसैन उम्र 60 वर्ष सा0 चम्पापुर तप्पा खजहनी तहसील शोहरतगढ थाना–शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर 3–सलमा खातून पुत्री अजीजूनिशा उर्फ जूबैदा खातून पत्नी मोबिन शेख सा0 चम्पापुर तप्पा खजहनी तहसील शोहरतगढ थाना–शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर हाल पता सा0–मझवा बनकट पोस्ट थाना इकौना जनपद बहराईच उम्र 30 वर्ष 4– अलमा खातून पुत्री अजीजूनिशा उर्फ जूबैदा खातून पत्नी शेहरे आलम सा0 चम्पापुर तप्पा खजहनी तहसील शोहरतगढ थाना–शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर हाल पता सा0–खडकुड्या पो0 थाना शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर उम्र 28 वर्ष 5–रेहाना पुत्री अजीजूनिशा उर्फ जूबैदा खातून पत्नी नदीम सा0 चम्पापुर तप्पा खजहनी तहसील शोहरतगढ सिद्धार्थनगर हाल पता सा0 पचपेडवा थाना पचपेडवा जनपद बलरामपुर उम्र 26 वर्ष 6– मुस्कान पुत्री अजीजूनिशा उर्फ जूबैदा खातून पत्नी तैमूर खान सा0 चम्पापुर तप्पा खजहनी तहसील शोहरतगढ थाना–शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर। उम्र 22 वर्ष 8–सारिक खान पुत्र अजीजूनिशा उर्फ जूबैदा खातून सा0 चम्पापुर थाना–शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर उम्र 19 वर्ष 9–फैजल पुत्र अजीजूनिशा उर्फ जूबैदा खातून सा0 चम्पापुर तप्पा खजहनी तहसील शोहरतगढ थाना–शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर। जरिये संरक्षिका हकीकी माता अजीजूनिशा उर्फ जूबैदा खातून उम्र 17 वर्ष

10–जासिफ खान पुत्र अजीजूनिशा उर्फ जूबैदा खातून सा0 चम्पापुर तप्पा खजहनी तहसील शोहरतगढ थाना–शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर। जरिये संरक्षिका हकीकी माता अजीजूनिशा उर्फ जुबैदा खातून उम्र 13 वर्ष

–विपक्षी स0–2

11. हामीद हुसैन पुत्र सब्बीर सा0 चम्पापुर तप्पा खजहनी तहसील शोहरतगढ थाना–शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर उम्र 66 वर्ष

विपक्षी स0–3

12–आम जनता

– विपक्षी स0–4

**तारीख पेशी 10–12–2026**

को यह सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदक ने संरक्षक/वारिस नियुक्त किए जाने के लिए यह आवेदन दिया है अतएव यह सूचना आपत्तिकर्ताओं को उपसंजाति और बाद की पेशी के प्रयोजन के लिए 10–12–2026 दिवस नियत करके निकाली जाती है कि यदि आपको/किसी अवधि के भीतर स्वयं अथवा अधिवक्ता द्वारा 10:00 बजे पूर्वाह्न के पूर्व न्यायालय के न्यायालय के उपसंजाति होकर अपनी आपत्ति पेश करें उक्त निर्णित अवधि के अवसान होने की दशा में आपकी किसी की आपत्ति न सुनी जायेगी और के आवेदन के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित किया जायेगा। सन् 2020 के के दिवस को दिनांकित

द0 हाकिम

## तीन दिवसीय अंतरकक्षीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू

**संवाददाता–गोरखपुर।** महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में बुधवार को अंतरकक्षीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें बीएससी, बीबीए और बीकॉम की छह टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन महाविद्यालय की क्रीड़ा परिषद के सदस्यों ने किया। इस अवसर पर क्रीड़ा परिषद के सचिव प्रो. महेश यादव सहित सदस्य डॉ. क्षमता श्रीवास्तव, डॉ. ब्रजेश कुमार गुप्ता, डॉ. विकास सिंह, डॉ. जितेंद्र कुमार और आंचल पांडेय मौजूद रहे। परिषद के सदस्यों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि तीन दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के समापन पर फाइनल मुकाबले के साथ विजेता टीमों के परिणाम घोषित किए जाएंगे।

दैनिक भारतीय बस्ती

**संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय**

**स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया कामप्लेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।**

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**

संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**

**अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–**

चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद

**लखनऊ कार्यालय–**

आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।

**गोरखपुर कार्यालय–**

इलाहीबाग गोरखपुर।

मो0 9336715406, 8400925463

**ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com dainikbhartiyabasti@gmail.com**